भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **439**

दिनांक **19** जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में दूध उत्पादन को सहायता देना

439. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दूध की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को देखते हुए महाराष्ट्र में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंकों और विश्व बैंक से सहायता लेने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में मांग के अनुसार दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) विश्व बैंक की निधियन सहायता के साथ, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I (एनडीपी-I) को 2242 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2012 से नवंबर 2019 के दौरान 18 प्रमुख डेयरी राज्यों में लागू किया गया था। इसका एक उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना और इस तरह तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना था।

भारत, दूध की घरेलू मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर है। देश में तथा महाराष्ट्र में दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत की तुलना में दुग्ध उत्पादन निम्नानुसार है:

	वर्ष **2019-20** में दुग्ध उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन)	वर्ष **2019** में दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत (मिलियन मीट्रिक टन)*
अखिल भारत	198.40	162.40
महाराष्ट्र	12.02	10.58

*वर्ष 2019 में राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण-I के तहत आयोजित 'भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग संबंधी अध्ययन' के अनुसार

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करने हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश की मांग के अनुसार दूध की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है:-

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन:- मिशन का उद्देश्य देशी बोवाईन नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी का आनुवंशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन तथा बोवाईनों की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित दूध खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए है।

iii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि: यह योजना मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण अवसंरचना और विनिर्माण सुविधाओं के सृजन/आधुनिकीकरण/विस्तार पर केंद्रित है।

iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता: राज्य सहकारी समितियों और परिसंघों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करना।

v. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: अन्य के साथ-साथ डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना की स्थापना के लिए अलग अलग उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु।

****